Part XI: Relations between the Union and the States

Part XI of the Constitution of India deals with the Relations between the Union and the States. It contains provisions regarding the distribution of powers and functions between the Union and the States, and the allocation of financial resources between them.

Article 245 empowers Parliament to make laws for the whole or any part of the territory of India, and provides for the distribution of powers between the Union and the States.

Article 246 provides for the distribution of legislative powers between Parliament and the State Legislatures, and lays down the subjects in respect of which Parliament and the State Legislatures can make laws.

Article 249 gives Parliament the power to legislate with respect to any matter in the State List if it is declared by a resolution of the Rajya Sabha to be necessary for the national interest.

Article 250 gives Parliament the power to make laws with respect to any matter in the State List during a national emergency.

Article 251 provides for the obligation of the States to comply with, and give effect to, the laws made by Parliament.

Article 252 allows Parliament to make laws for two or more States with the consent of the States concerned, and to form a new State or alter the boundaries of existing States.

Article 256 provides for the obligation of the States to comply with the laws made by Parliament and the existing laws, and gives the President the power to give directions to the States.

Article 257 provides for the financial relations between the Union and the States, and lays down the obligation of the States to follow the directions given by the President with respect to financial matters.

Overall, Part XI of the Constitution of India lays down the provisions regarding the distribution of powers and functions between the Union and the States, and the allocation of financial resources between them, and aims to ensure the harmonious functioning of the federal system in India.

भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध

भारत के संविधान का भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के वितरण और उनके बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के संबंध में प्रावधान हैं।

अनुच्छेद 245 संसद को भारत के पूरे क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है, और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधानसभाओं के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान करता है, और उन विषयों को निर्धारित करता है जिनके संबंध में संसद और राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं।

अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है यदि यह राज्य सभा के एक संकल्प द्वारा राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक घोषित किया जाता है।

अनुच्छेद 250 संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 251 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए राज्यों के दायित्व का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 252 संसद को संबंधित राज्यों की सहमति से दो या दो से अधिक राज्यों के लिए कानून बनाने और एक नया राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों की सीमाओं को बदलने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद 256 संसद और मौजूदा कानूनों द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करने के लिए राज्यों के दायित्व का प्रावधान करता है, और राष्ट्रपति को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देता है।

अनुच्छेद 257 संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को प्रदान करता है, और वित्तीय मामलों के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए राज्यों के दायित्व को निर्धारित करता है।

कुल मिलाकर, भारत के संविधान का भाग XI संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के वितरण और उनके बीच वित्तीय संसाधनों के आवंटन के प्रावधानों को निर्धारित करता है, और इसका उद्देश्य भारत में संघीय प्रणाली के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना है।